

सेना प्रमुख को प्रादेशिक सेना को सहयोग के लिए जुटाने का अधिकार, केंद्र सरकार का बड़ा फैसला

नई दिल्ली। भारत सरकार देश की सुरक्षा को और पाकिस्तान को मारक जलावा देने के लिए कई बड़े फैसले ले रही है। अब यह सरकार को सेना प्रमुख को बड़ा अधिकार दिया है। जिसके तहत उन्हें सेना प्रमुख को स्थापित किया गया था, ने पिछले साल अपनी 75वीं वर्षगांठ मनाई थी। यह बल न सिर्फ युद्ध के समय देश की सेवा करता है, बल्कि अपना राहत, पर्यावरण सुरक्षा और मानवीय मदद में भी सक्रिय भूमिका निभाता है। टॉप पूरी तरह सेना के समय जुड़ा हुआ है और इसके जबाबों को उनकी बहादुरी और सेवा के लिए कई पुरस्कार भी मिल चुके हैं।

भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे सैन्य तनाव के बीच केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। अब सेना प्रमुख को अधिकार दिया गया है कि वे प्रादेशिक सेना के हर अफसर और सैनिक को तैनात कर सकते हैं, ताकि जरूरत पड़ने पर नियमित सेना की मदद की जा सके या उसकी ताकत बढ़ावा दी जा सके।

रक्षा मंत्रालय के सैन्य मामलों के विभाग ने 6 मई को इस संबंध में अधिसूचना जारी की है। इसमें, कहा गया है कि यह आदेश 10 फरवरी 2025 से प्रभावी होगा और 9 फरवरी 2028 तक लागू रहेगा। इसका मतलब है कि अगली तीन सालों तक सेना प्रमुख के

यूपी को 'वन ट्रिलियन डॉलर' इकॉनमी बनाने में विश्व बैंक का अहम रोल: योगी

अवधनामा ब्यूरो

- विश्व बैंक हमेशा उपर्युक्त वैज्ञानिकों की दिशा में बढ़ा भारीदार बनकर उभरता है।
- योगी आदित्यनाथ से मिले अजय बंगा।
- उल्लेखनीय है कि यूपी एप्रिस प्रोजेक्ट 4 हजार करोड़ की।



पहलुओं में देख बनाया जाएगा।

इन दोनों कार्यक्रम को लान्च करते हुए सूचीय योगी ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश देश की विकास गाथा का पर्याय है, आज सरे विश्व ने मान लिया है कि उत्तर प्रदेश बैंकरियर नहीं बल्कि भारत का ग्राह इंजन है। दोनों ही कार्यक्रम प्रदेश के 'वन ट्रिलियन डॉलर' की इकॉनमी बनने का समान सकार करते हैं। उन्होंने यूपी-एप्रिस प्रोजेक्ट में विश्व बैंक की सहभागिता का आभार जताते हुए कहा कि यूपी-एप्रिस के जरिए प्रदेश के कृषि उत्पादकता को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी।

10 लाख किसानों को प्रत्यक्ष रूप से मिलेगा लाभ

इस परियोजना से 10 लाख किसानों को प्रत्यक्ष रूप से लाभ होगा, जिसमें 30 प्रतिशत हिस्सेदारी महिलाओं की होगी। वर्धमान रहिए उत्पादक समझों के परियोजना से जोड़ा जाएगा। इसके अलावा 500 किसानों को सर्वोत्तम कृषि तकनीकी जागरूकी के लिए विदेशी में भेजा जाएगा। इससे छोटे किसानों को सशक्त बनाने और क्षेत्रीय विश्वमताओं को ऊर्जा करने में मदद मिलेगी।

परियोजना के अंतर्गत पूर्वी उत्तर प्रदेश के 21 जिले शासकीय बहाइँ, बलरामपुर, गोडा, सिद्धार्थनगर, वस्ती, महाराष्ट्र, संतकबीर नगर, कुशीनगर, गोपीनगर, देवेश्वर, आजमगढ़, मजू, जौनपुर, बलिया, गाजिपुर, वाराणसी, चंदौली, मीरजापुर, सोनबद और संत रीवासन नगर तथा बुदेलखण्ड के जानौर, झांसी, हमीरपुर, महेश्वर, बांदा, लिलितपुर और विरचकू जैसे जिलों के किसान लाभाभिष्ठ होंगे।

परियोजना के संचालन हो, विश्व बैंक हमेशा

उत्तर प्रदेश की उन्नति में बढ़ा भारीदार बनकर उभरता है। उन्होंने कहा कि आज का दिन कई मायनों में महत्वपूर्ण है।

आज प्रदेश को कृषि और आर्टिफिशियल इंटीलिजेंस के विभिन्न